

भारत का डीप टेक विज़िन

यह एडिटोरियल 11/09/2024 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "India's march towards deep tech" लेख पर आधारित है। इसमें भारत के पारंपरिक सॉफ्टवेयर से 'डीप टेक' की ओर आगे बढ़ने की चर्चा की गई है, जो जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल जैसी वैश्वकि चुनौतियों के समाधान की आवश्यकता से प्रेरित है। भारत प्रबल सरकारी समर्थन और उन्नत स्टार्ट-अप परिवर्तित के साथ वैश्वकि डीप-टेक परिवृश्य में अग्रणी भूमिका निभाने के लिये स्वयं को तैयार कर रहा है।

प्रलिमिस के लिये:

स्काईरूट एयरोस्पेस, राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कवांटम टेक्नोलॉजीज और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय मशिन, राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति 2023, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, विक्रम-एस रॉकेट, राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटर्स मशिन।

मेन्स के लिये:

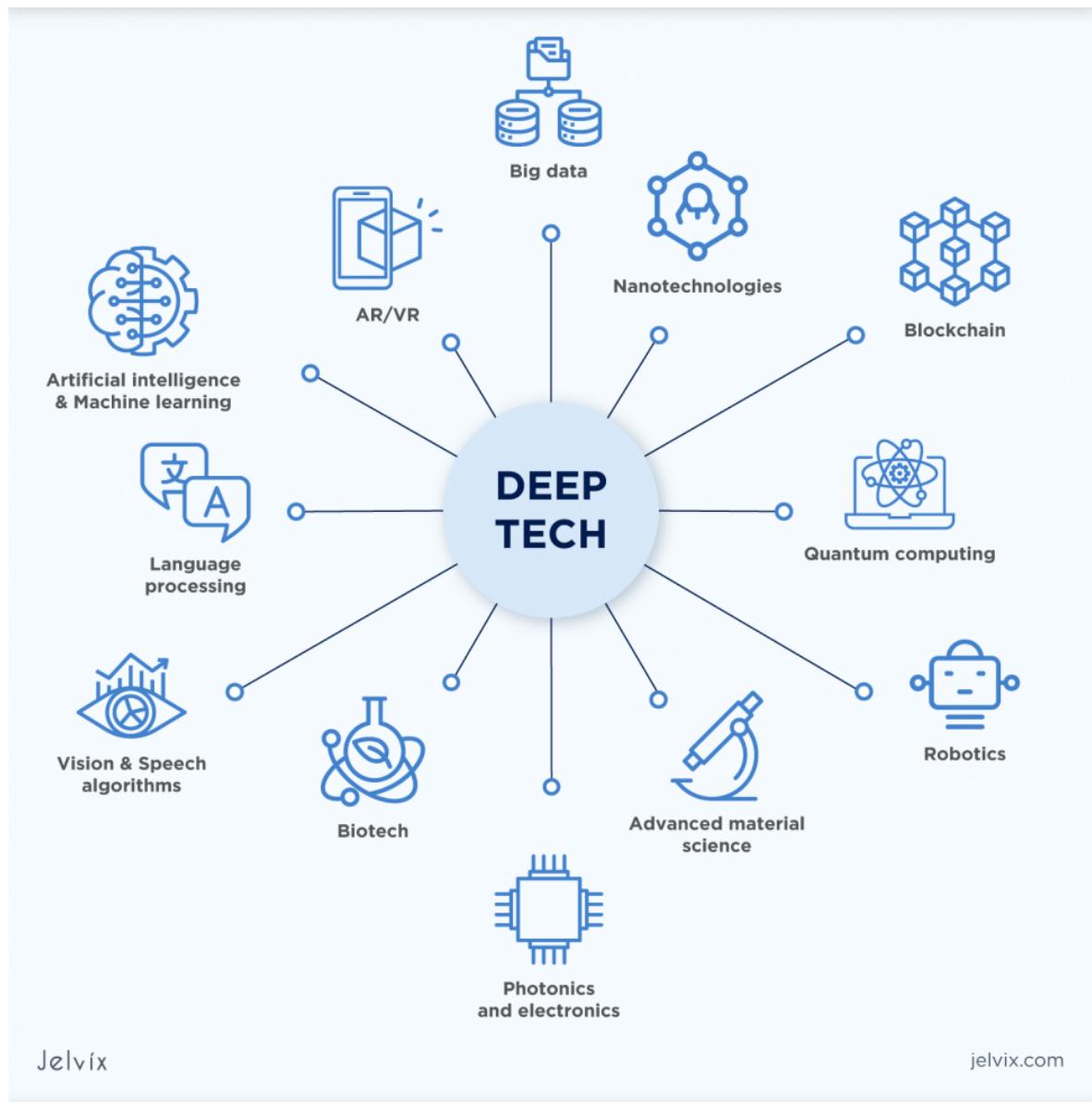
भारत में डीप टेक के विकास के प्रेरक, भारत में डीप टेक क्षेत्र के विकास से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ।

भारत का तकनीकी परिवृश्य पारंपरिक रूप से सॉफ्टवेयर और उपभोक्ता इंटरनेट पर केंद्रित रहा है। हालाँकि जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य सेवा जैसी वैश्वकि चुनौतियों के समाधान की बढ़ती आवश्यकता ने उसे 'डीप टेक' (deep tech) की ओर आगे बढ़ने के लिये प्रेरित किया है। ये अत्यधिक स्टार्ट-अप अभियानों के सूजन के लिये वैज्ञानिक खोज और इंजीनियरिंग नवाचार का लाभ उठा रहे हैं।

भारतीय नवाचार की यह नई लहर AI, रोबोटिक्स और जैव प्रौद्योगिकियों जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ जटिल समस्याओं को संबोधित कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण से संबद्ध स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace) और ड्रोन से संबद्ध आईडिया फोर्ज (Idea Forge) जैसे स्टार्ट-अप ऐसे अग्रणी समाधान विकास कर रहे हैं, जिनमें कभी स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व रहा था। राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्ट-अप नीति (Deep Tech Startup Policy) और शोध संस्थानों के लिये वित्तीयों में वृद्धि जैसी पहलों के साथ सरकार भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस समर्थनकारी पारिवर्तित के साथ भारत की सुदूर STEM शिक्षा और जीवन्त स्टार्ट-अप संस्कृति देश को वैश्वकि डीप टेक दौड़ में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकने के लिये तैयार कर रही है। जबकि चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जैसे विनियमन संबंधी चुनौतियों के बीच आगे बढ़ना और प्रतिभा को आकर्षित करना, लेकिन डीप टेक की दिशा में भारत के प्रयास देश को नवाचार में अग्रणी बनाने की व्यापक क्षमता रखते हैं।

डीप टेक (Deep Tech) क्या है?

- परिचय: 'डीप टेक' या 'डीप टेक्नोलॉजी' वैज्ञानिक खोजों और इंजीनियरिंग सफलताओं से प्रेरित है, जो सैद्धांतिक अवधारणाओं को वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों में साकार करती है。
 - वृद्धशील सुधारों पर केंद्रित पारंपरिक तकनीक के विपरीत डीप टेक उद्यम प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ के लिये अभिनव प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाते हैं, जिसके लिये प्रायः सुविराग एवं अनश्चित अनुसंधान एवं विकास (R&D) प्रक्रयाओं से गुज़रते हैं।
- डीप टेक की मुख्य विशेषताएँ:
 - वैज्ञानिक गहनता: आधारभूत वैज्ञानिक खोजों या इंजीनियरिंग नवाचारों में नाहिति।
 - सुविराग अनुसंधान एवं विकास चक्र: डीप टेक के लिये आमतौर पर अनुसंधान एवं विकास की विस्तारित समयावधि आवश्यक होती है।
 - उच्च पूंजी गहनता: सामान्यतः विशेषित उपकरण और प्रतिभा में प्रयोगपत पूंजी निविश की आवश्यकता होती है।
 - विद्युतनकारी प्रभाव की क्षमता: इसमें नए बाज़ार के सृजन या मौजूदा बाज़ारों को व्यापक रूप से रूपांतरित करने की सक्षमता होती है।
- डीप टेक के मुख्य क्षेत्र: AI एवं मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन, कवांटम कंप्यूटर्स मशिन, बायोटेक्नोलॉजी एवं संथिटिक बायोलॉजी, एडवांस्ड मैटेरियल्स साइंस, नैनोटेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन और डिस्ट्रिबियूटेड लेजर टेक्नोलॉजी आदी।



- **डीप टेक में भारत की स्थिति:** भारत वर्तमान में अपने 3,600 स्टार्ट-अप्स के साथ (जिन्हें वर्ष 2023 में 850 मलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय प्रबल घोषणा किया गया) वैश्वक सतर पर शीर्ष 9 डीप टेक पारंतिरों में छठे स्थान पर है।
 - संस्थापक और नविशक **कूटरमि बुद्धिमत्ता (AI)** पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जहाँ वर्ष 2023 में 74% नए डीप टेक स्टार्ट-अप्स AI पर केंद्रित थे, जबकि वित्तीय प्रबल स्टार्ट-अप के 86% AI पर केंद्रित थे।
 - पेटेंट फाइलिंग में भी AI का ही वर्चस्व है, जो सभी डीप टेक पेटेंटों में 41% हसिसेदारी रखता है।

भारत में डीप टेक के विकास को प्रोत्साहन देने वाले प्रमुख कारक

- **सरकार का नीतिगत प्रोत्साहन:** भारत सरकार की अग्रसरकर्या नीतियाँ डीप टेक के विकास को बढ़ावा देने में सहायक रही हैं।
 - 8,000 करोड़ रुपए के बजटीय परिविय के साथ लॉन्च किया गया **क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मशिन (National Mission on Quantum Technologies and Applications)**। इस प्रतिविद्धता की पुष्टी करता है।
 - **राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्ट-अप नीति 2023 का मसौदा** प्रौद्योगिकीय विकास में तेज़ी लाने और वैश्वक प्रतिविद्धता को बढ़ाने पर लक्ष्यता है।
 - अनुसंधान नेशनल रसिरच फाउंडेशन (ANRF) अपनी 1 लाख करोड़ रुपए की निधि के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान में भारी निवेश कर रहा है।
 - इन पहलों से डीप टेक नवाचार के लिये अनुकूल वातावरण का निर्माण होता है, जहाँ वे वित्तीय समर्थन और ऐसे नियामक ढाँचे प्रदान करते हैं जो प्रयोग करने और जोखिम उठाने को प्रोत्साहित करते हैं।
- **उद्यम पूँजी निवेश में वृद्धि:** वर्तमान में डीप टेक वैश्वक वार्षिक उद्यम पूँजी निवेश में लगभग 20% की हसिसेदारी रखती है, जो काप्रिक दशक पहले 10% थी।
 - अक्टेले 2023 में ही, आरथकि मंदी के बावजूद, डीप टेक स्टार्ट-अप्स ने वैश्वक सतर पर लगभग 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए।
 - यह प्रवृत्ति भारत में भी दिखाई देती है, जहाँ Observe.AI जैसी कंपनियों ने अपनेकंवर्सेशनल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिये 214 मलियन अमेरिकी डॉलर से अधिकी की धनराशि जुटाई है।

- दीर्घावधकी और उच्च-जोखमिपूरण टेक परयोजनाओं को समर्थन देने में नविशकों की बढ़ती उचिति एक परपिक्व पारस्थितिकी तंत्र और भारत की नवोन्मेषी कषमताओं में बढ़ते भरोसे का संकेत देती है।
- **स्वदेशी समाधानों की बढ़ती मांग:** आत्मनिर्भरता पर भारत का ज़ोर, वशिष्ठ रूप से रक्षा और अंतरकिंश जैसे रणनीतिकि क्षेत्रों में, स्वदेशी डीप टेक समाधानों की मांग को प्रेरित कर रहा है।
 - स्काइरुट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace) द्वारा वर्ष 2022 में **क्रिएम-S रॉकेट** का सफल प्रक्षेपण इस प्रवृत्तिको परलिक्षण करता है।
 - रक्षा एवं सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिये **आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी (ideaForge Technology)** के उन्नत ड्रोन भी इस बात की पुष्टीकरते हैं कि डीप टेक क्षेत्र के स्टार्ट-अप्स द्वारा महत्वपूरण राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूरतीकी जा रही है।
 - यह मांग न केवल डीप टेक नवाचारों के लिये एक तैयार बाज़ार उपलब्ध कराती है, बल्कि भारत की वशिष्ठ आवश्यकताओं के अनुरूप अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास को भी प्रोत्साहन देती है।
- **सशक्त STEM प्रतभा पूल:** विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (Science, Technology, Engineering, and Mathematics- STEM) शिक्षा में भारत का मजबूत आधार डीप टेक नवाचार के लिये एक समृद्ध प्रतभा पूल प्रदान करता है।
 - प्रतविर्ष 1.5 मिलियन से अधिक इंजीनियरिंग स्नातकों के साथ भारत के पास तकनीकी वशिष्ठज्ञता का व्यापक भंडार मौजूद है।
 - चुनौती इसमें नहित है कि इस प्रतभा को कसि प्रकार बनाए रखा जाए और इन्हें डीप टेक उद्यमता की ओर आगे बढ़ाया जाए। उद्योग-अकादमिक सहयोग में वृद्धि के साथ इस चुनौती को संबोधित करने का प्रयास किया जा रहा है।
- **बड़ी चुनौतियों के समाधान पर फोकस:** भारत में डीप टेक स्टार्ट-अप्स स्वास्थ्य सेवा, जलवायु परविरतन और संवहनीय उरजा जैसे क्षेत्रों की बड़ी चुनौतियों के समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
 - बायोकॉन (Biocon) और सिंजेन (Syngene) जैसी बायोटेक कंपनियाँ जीनोमिक्स एवं वैयक्तिकि चकितिसा अनुसंधान में अग्रणी स्थान रखती हैं।
 - इलेक्ट्रॉनिक मोबाइलिटी समाधानों पर सेल प्रोपल्शन (Cell Propulsion) का कार्य प्रविहन और प्रयावरण संबंधी चुनौतियों को संबोधित करता है।
 - उच्च प्रभावपूरण एवं दीर्घकालिक समाधानों पर यह केंद्रित ध्यान न केवल प्रतभा और नविश को आकर्षित करता है, बल्कि भारतीय डीप टेक स्टार्ट-अप्स को वैश्वकि समस्या समाधानकरता के रूप में स्थापित भी करता है, जिससे उनकी प्रासंगिकता और बाज़ार क्षमता में वृद्धि होती है।

भारत में डीप टेक क्षेत्र के विकास की राह की प्रमुख बाधाएँ

- **सुदीर्घ प्रयोजना अवधिकी पहेली (Long Gestation Conundrum):** डीप टेक नवाचारों को प्रायः वाणिज्यिकरण से अनुसंधान एवं विकास की सुदीर्घ अवधिकी आवश्यकता होती है।
 - यह सुदीर्घ प्रयोजना अवधिअधिकांश उद्यम पूँजी फर्मों के सामान्य 3-5 वर्ष के नविश दायरे से टकराव रखती है, जिससे डीप टेक स्टार्ट-अप्स के लिये वित्तीय अंतराल उत्पन्न होता है।
 - विकास समयसीमा और नविशकों की अपेक्षाओं के बीच यह असंगतिया तालमेल की कमी नवाचार को, वशिष्ठ रूप से जैव प्रौद्योगिकी एवं उन्नत सामग्री जैसे पूँजी-गहन क्षेत्रों में, बाधित कर सकती है।
- **प्रतभा की रस्साकशी (Talent Tug-of-War):** हालाँकि भारत बड़ी संख्या में STEM स्नातकों का उत्पादन करता है, लेकिन गहन प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में वशिष्ठज्ञ प्रतभाओं की व्यापक कमी पाई जाती है।
 - केवल 3% इंजीनियर ही AI, मशीन लर्निंग, डेटा विज्ञान और मोबाइल विकास जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी कौशल रखते हैं।
 - अत्याधुनिक नौकरियों में रोजगार-योग्यता (employability) औसतन 1.7% ऊँकी गई है।
 - वैश्वकि तकनीकी केंद्रों (tech hubs) की ओर प्रतभा पलायन (brain drain) इस मुद्दे की गंभीरता को और बढ़ा देता है। अप्रैल 2022 और मार्च 2023 के बीच कनाडा आने वाले वैश्वकि टेक इंडस्ट्री कर्मकारों में सबसे बड़ा समूह भारतीयों का था।
 - प्रतभा की कमी के कारण अनुसंधान एवं विकास के प्रयास धीमे हो जाते हैं और डीप टेक क्षेत्र के स्टार्ट-अप्स के लिये नवाचार की लागत बढ़ जाती है।
- **विनियमक भूलभूलैया (Regulatory Labyrinth):** डीप टेक प्रायः प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक स्तर पर कार्यरत होता है, जहाँ विनियमन या तो मौजूद ही नहीं होते या तो जीसे उभर रहे होते हैं।
 - उदाहरण के लिये, भारत द्वारा वर्ष 2018 और 2021 के बीच ड्रोन नीतितैयार किये जाने के दौरान ड्रोन नियमाताओं को लगातार बदलते नियमों का सामना करना पड़ा।
 - ‘जीन एडटिपि’ या AI जैसे उभरते क्षेत्रों में स्पष्ट नियमक ढाँचे का अभाव स्टार्ट-अप्स के लिये अनशिचितिता पैदा करता है।
 - यह नियमक अस्पष्टता नविश को बाधित कर सकती है और नवीन प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण की प्रक्रिया को मंद कर सकती है।
- **बाज़ार की तैयारियों से असंगति (Market Readiness Mismatch):** कई डीप टेक नवाचार इतने उन्नत होते हैं कि वे बाज़ार की तैयारी के दायरे से आगे नकिल जाते हैं, जिससे उनके अंगीकरण की चुनौती उत्पन्न होती है।
 - उदाहरण के लिये, जबकि **BosonQ Psi** जैसी क्वांटम कंप्यूटिंग क्षेत्र के स्टार्ट-अप व्यापक प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भारत में क्वांटम समाधानों का बाज़ार अभी भी नवजात अवस्था में है।
 - नवाचार और अंगीकरण के बीच यह अंतराल ‘पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया की प्रायोगकि समस्या’ (chicken and egg problem) को जन्म दे सकता है, जहाँ बाज़ार में आकर्षण की कमी भविष्य के नविश को रोकती है, जबकि नविश की कमी बाज़ार के विकास को मंद कर देती है।
- **अवसंरचना की कमी:** डीप टेक अनुसंधान के लिये प्रायः वशिष्ठ अवसंरचना और परीक्षण सुवधाओं की आवश्यकता होती है।
 - भारत विश्व के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की कंप्यूटर अवसंरचना में 2% से भी कम की हस्सेदारी रखता है, जो कि अमेरिका और चीन जैसे देशों की तुलना में कई गुना कम है, जो संयुक्त रूप से लगभग 60% हस्सेदारी रखते हैं।

- इस तरह की अवसंरचना की कमी से न केवल स्टार्ट-अप्स की लागत बढ़ती है, बल्कि निवाचार की गतिभी धीमी हो जाती है।
- जबकि **राष्ट्रीय सुरक्षणीय मरिन** जैसी पहलें कुछ अंतरालों को दूर करने का प्रयास करती है, फरि भी अवसंरचना की कमी वभिन्न डीप टेक क्षेत्रों के लिये गंभीर बाधा बनी हुई है।
- बौद्धिक संपदा संबंधी चुनौतियाँ: बौद्धिक संपदा (IP) को सुरक्षित रखना और उसका बचाव करना डीप टेक स्टार्ट-अप्स के लिये महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत में यह एक जटिल चुनौती बनी हुई है।
 - **वैश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization)** की वर्ष 2023 की रपोर्ट में भारत को नवाचार में वैश्वकि स्तर पर 40वाँ स्थान दिया गया, जो सुदृढ़ बौद्धिक संपदा संरक्षण की आवश्यकता को उजागर करता है।
 - वैश्वकि पेटेंट फाइलिंग एवं प्रवरतन की उच्च लागत और भारत में अपेक्षाकृत सुस्त पेटेंट अनुदान प्रकरण (जो अमेरिका में 23 माह की तुलना में औसतन 58 माह है) के कारण भारतीय डीप टेक स्टार्ट-अप्स वैश्वकि नवाचार दौड़ में अलाभ की स्थिति का सामना कर सकते हैं।
- वित्तपोषण की कमी: नैसकॉम (NASSCOM) और जिनोव (Zinnov) की रपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 2023 में भारतीय डीप टेक स्टार्ट-अप्स के लिये वित्तपोषण में 77% की गिरावट आई, जहाँ कुल निवेश घटकर 850 मलियन अमेरिकी डॉलर रह गया और सौदों की संख्या में 25% की कमी आई।
 - प्रमुख चुनौतियों में वसितार के लिये वित्तपोषण सुरक्षित करना, प्रतभिका आकर्षित करना और वैश्वकि वसितार करना शामल है।
 - जून 2022 की तुलना में निवेशक पूल में 60% की कमी आई है, जहाँ बड़े वैश्वकि निवेशक विशेष रूप से अनुपस्थित हैं, जिसके कारण नमिन-जोखमिपूर्ण सीड-स्टेज उदयमों (seed-stage ventures) को प्राथमिकता दी जा रही है।

डीप टेक के विकास में गतिलाने के लिये कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?

- ‘डीप टेक कलस्टर्स’ की स्थापना करना: बोस्टन के केंडल स्क्वायर (Kendall Square) जैसे सफल वैश्वकि उदाहरणों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए प्रमुख भारतीय शहरों में विशिष्ट डीप टेक कलस्टर्स का सृजन किया जाए।
 - ये कलस्टर्स स्टार्ट-अप्स, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग भागीदारों को एक मंच पर ला सकेंगे।
 - उदाहरण के लिये, बैंगलुरु में AI एवं रोबोटिक्स कलस्टर की स्थापना की जा सकती है, जबकि हैदराबाद में एयरोस्पेस एवं डफिंस टेक पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।
 - सरकार प्रमुख हातिधारकों को आकर्षित करने के लिये कर प्रोत्साहन और सब्सिडीयुक्त अवसंरचना की पेशकश कर सकती है।
 - इस दृष्टिकोण से सहयोग को बढ़ावा मिलिए, स्टार्ट-अप्स के लिये अवसंरचना की लागत कम होगी और प्रतभिका एवं संसाधनों का एक विशाल भंडार तैयार होगा।
- डीप टेक-केंद्रित उदयम निधि: सरकार-समरथति उदयम निधि (venture funds) स्थापित किये जाएँ, विशेष रूप से डीप टेक उदयमों को आवंटित किया जा सकता है।
 - स्टार्ट-अप्स के लिये फंड ऑफ फंड्स (Fund of Funds for Startups- FFS) के 10,000 करोड़ रुपए का 1% विशेष रूप से डीप टेक उदयमों को आवंटित किया जा सकता है।
 - नजी वैचर कैपिटल फर्मों के साथ साझेदारी कर मिश्रित वित्त मॉडल का सृजन किया जाए, जहाँ सरकारी निधियों नजी निवेशों के जोखिम को कम करती है।
 - यह दृष्टिकोण पूँजी-गहन, लंबी परियोजना अवधिकी डीप टेक परियोजनाओं के लिये वित्त पोषण की कमी को पूरा करेगा, जिससे कार्डिनल एयरोस्पेस जैसे अधिकाधिक स्टार्ट-अप्स को अपने नवाचारों को बाज़ार में लाने में मदद मिलिए।
- ‘रेगुलरटी सैंडबॉक्स’ (Regulatory Sandboxes): वभिन्न डीप टेक क्षेत्रों में रेगुलरटी सैंडबॉक्स को क्रियान्वित किया जाए, ताकि स्टार्ट-अप्स को नियंत्रित वातावरण में सरल वनियमों के साथ नवाचारों का परीक्षण करने की अनुमतिमिलि सके।
 - फनिटेक के लिये RBI के रेगुलरटी सैंडबॉक्स को AI, बायोटेकनोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में भी अनुकूलन के साथ अपनाया जा सकता है।
 - उदाहरण के लिये, स्वचालित वाहनों के लिये एक सैंडबॉक्स ‘एथर एनर्जी’ (Ather Energy) जैसी कंपनियों को नियंत्रित क्षेत्रों में उन्नत स्वचालित सुविधाओं का परीक्षण करने की अनुमतिदि सकता है।
 - यह दृष्टिकोण वनियामक स्पष्टता प्रदान करेगा, नई प्रौद्योगिकियों के विकास एवं अंगीकरण को गतिप्रदान करेगा और वनियामकों को सूचना-संपन्न नीतियाँ तैयार करने में मदद करेगा।
- डीप टेक शक्तिका पहल: सनातक और सनातकोत्तर स्तर पर विशिष्ट डीप टेक पाठ्यक्रम के नियमान के लिये शीर्ष IITs और नजी संस्थानों के साथ सहयोग का नियमान किया जाए।
 - प्रधानमंत्री रसिरच फेलोशिप योजना (PMRF) की तरह उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्योग-प्रायोजनी पीएचडी कार्यक्रम शुरू किया जाए।
 - यह पहल डीप टेक विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाने पर लक्षित हो सकती है, जिससे इस क्षेत्र की कंपनियों (जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग में QNu Labs) के समक्ष विद्यमान प्रतभिका की कमी की समस्या को संबोधित किया जा सकता है।
- खुले नवाचार प्लेटफॉर्म: प्रमुख डीप टेक क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय खुले नवाचार प्लेटफॉर्म विकसित किये जाएँ, जहाँ स्टार्ट-अप्स, कॉरपोरेट्स और शक्तिकावदों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाया जाए।
 - इन्हें ‘ग्लोबल साउथ कोवडि-19 डिजिटिल इनोवेशन चैलेंज’ जैसी सफल पहलों के अनुरूप तैयार किया जाए।
 - उदाहरण के लिये, Niramai जैसे स्टार्ट-अप (जो स्तन कैंसर का पता लगाने के लिये AI का उपयोग करता है) को प्रमुख अस्पताल शुंखलाओं और चकितिसा अनुसंधान संस्थानों के साथ संबद्ध करने में ‘AI फॉर हेलथकेयर’ जैसा कोई प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण भूमिका नभिन्न सकता है।
 - यह दृष्टिकोण डीप टेक नवाचारों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं के साथ संरेखित करने में मदद करेगा और उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिये बाज़ार में आकर्षण पैदा करेगा।
- डीप टेक वाणिज्यिकरण कोष: प्रयोगशालाओं से विषयन योग्य उत्पादों तक अनुसंधान के संक्रमण का समरथन करने के लिये डीप टेक

वाणिज्यीकरण कोष (Deep Tech Commercialization Fund) की स्थापना की जाए।

- उन्नत सामग्री, जैव प्रौद्योगिकी और ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए धन आवंटित किया जाए।
- इसे अमेरिकी ऊर्जा विभाग के प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण कोष (Technology Commercialization Fund) जैसे सफल कार्यक्रमों के आधार पर तैयार किया जा सकता है।
- उदाहरण के लिये, यह कोष IISc बैंगलोर की सफल सॉलडि-स्टेट बैटरी प्रौद्योगिकी का वाणिज्यीकरण करने हेतु स्थापित स्टार्ट-अप को सहायता प्रदान कर सकती है।
- वैश्वक डीप टेक गठबंधन (Global Deep Tech Alliances): सलिकॉन वैली, तेल अवीव और सगिपुर जैसे वैश्वक नवाचार केंद्रों के साथ एक रणनीतिक डीप टेक गठबंधन का निर्माण किया जाए।
 - द्विपक्षीय नवाचार कोष, संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम और प्रतभिमिय पहल की स्थापना की जाए।
- उदाहरण के लिये, क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर भारत-इजराइल द्विपक्षीय कार्यशाला (IQQT-2022) क्वांटम कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में प्रगतिकी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

निष्कर्ष

भारत का टेक प्रदिश्य पारंपरिक सॉफ्टवेयर से डीप टेक की ओर एक व्यापक बदलाव को चहिनति कर रहा है, जो जलवायु परवर्तन और स्वास्थ्य सेवा जैसी वैश्वक चुनौतियों से प्रेरित है। उभरती चुनौतियों का समाधान करने और क्षेत्र के विकास में गतिलाने के लिये, NASSCOM ने एक बहुआयामी रणनीतिकी अनुशंसा की है, जिसमें नवाचार समूहों को सुदृढ़ करना, पेशेंट कैपिटल एवं कंप्यूटिंग अवसंरचना तक पहुँच बढ़ाना, राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति के क्रियान्वयन में गतिलाना, IP ढांचे में सुधार करना और एक सुदृढ़ प्रतभिमिय पाइपलाइन विकसित करना शामिल है। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, भारत की STEM प्रतभिमिय और उद्यमशीलता की भावना इन उपायों से समर्थन पाकर डीप टेक नवाचार में देश को अग्रणी भूमिका प्रदान कर सकती है।

अभ्यास प्रश्न: 'डीप टेक' का उभार वैश्वक चुनौतियों का समाधान करने और प्रौद्योगिकीय सीमाओं को पुनर्परभाषित करने में एक प्रवर्तनकारी शक्ति के रूप में हो रहा है। भारत के भविष्य के विकास को आकार देने में डीप टेक की भूमिका पर चरचा कीजिये, जहाँ इसके संभावित लाभों और चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. अटल नवप्रवर्तन (इनोवेशन) मिशन कसिके अधीन स्थापित किया गया है? (2019)

- (a) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- (b) शरम और रोजगार मंत्रालय
- (c) नीति (NITI) आयोग
- (d) कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय

उत्तर: (c)

प्रश्न: कोवडि-19 महामारी ने वश्वभर में अभूतपूर्व तबाही उत्पन्न की है। तथापि, इस संकट पर विजय पाने के लिये प्रौद्योगिकीय प्रगति का लाभ स्वेच्छा से लिया जा रहा है। इस महामारी के प्रबन्धन के सहायतारथ प्रौद्योगिकी की खोज कैसे की गई, उसका एक विवरण दीजिए। (2020)